CHENNAI		
8.	New Port at En-norc	593.90
9.	Further Extension of Container Terminal	52.10
VISAKHAPATNAM		
10.	LPG jetty in Outer Harbour-	24.12
11.	Multipurpose Cargo berth in Outer Harbour.	37.70
PARADIP		
12.	Mechanised Coal handling facilities.	587.41

कांडला पत्तन के विस्तार के लिए योजना

880. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कांडला पत्तन न्यास के विस्तार और गोदियों के निर्माण के लिए कोई योजना बनाई हैं

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त पत्तन की किन-किन योजनाओं और विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई हैं

(ग) क्या कतिपय परियोजनाएं मंजूरी के लिए सरकार के पास लम्बित/विचाराधीन है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या हैं और वे परियोजनाएं कब से लम्बित/विचाराधीन हैं

(ड.) इनकी अनुमति लागत कितनी हैं

(च) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना हैं, और

(छ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) कांडला पत्तन में कार्यान्वित की जा रही इन परियोजनाओं की सूची जिनकी लागत 5 करोड़ रू. अथवा उससे अधिक हैं:

क्रम सं.	पत्तन/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रू.)	संस्वीकृति की तारीख	पुरा होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4	5
कांडला				
1.	तीसरी तेल जैटी का निर्माण	19.67 (संशोधित 29.8)	15.1.92	31.3.98
2.	8वीं सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण	18.82 (संशोधित 49.94)	9.6.94	31.8.99
3.	सभी उपकरणों आदि के साथ 66 कि.वा./11 कि.वा. के विघुत उपकेन्द्र की व्यवस्था	15.74	12.7.94	मार्च, 98
4.	4 विघूत व्हार्फ क्रेनों की खरीद	21.19	29.3.95	28.4.98
5.	चौथी तेल जैटी का निर्माण	25.12	13.2.96	12.2.2000

(ग) से (ड.) 150.00 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से हापर निकर्षक कच्छ वल्लभ को बदलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही हैं।

(च) और (छ) संबंधित औपचारिकताओं के पूरे होते ही प्रस्ताव को संस्वीकृति दे दी जाएगी।

Report on the performance of Indian Shipping Industry

881. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the D.G. of Shipping Mr. Michael Pinto is reported to have said that Indian Shipping Industry's performance bad been uneven for a very long time;

(b) if so, whether a report is being finalised on a major new snipping policy covering import and financing regulations for the purchase of new ships; and

(c) if so, the details in this regard; and by when Government propose to bring out this report?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) No, Sir. In order to consider the issues raised by the shipping industry from time to time to formulate a National Shipping Policy, a Committee under the Chairmanship of Director General of Shipping has been formed in March, 1997. The Committee is likely to submit its report by end July, 1997.

Port in West Godavari District in Andhra Pradesh

882. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have received a specific proposal for a Rice/Food Grain Port in West Godavari district, Andhra Pradesh;

(bi if so the full details and salient

(c) whether the proposal has been made by an individual or organisations;

(d) the details of the proposes including name;

(e) whether any attempt has been made to invite discussions on this proposal; and

(f) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) and (b) Yes, Sir. A proposal has been received for development of a dedicated Rice/Grain Port at Narsapur in West Godavari District in Andhra Pradesh with the suggestion that the area is a rich producer of rice and can furnish sufficient cargo for successful operation of a dedicated Rice/ Grain Port.

(c) and (d) The proposal is from Dr. P. Pulla Rao of West Godavari District, Andhra Pradesh and has been forwarded through some Members of Parliament.

(e) and (f) The matter has been examined. Since Narsapur is a minor port, the responsibility for its development lies with the State Government of Andhra Pradesh.

सडक परिवहन की माग मे वार्षिक वृध्दि

883. **श्री राम जेठमलानी :**

प्रो. राम कापसे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्षो के दौरान देश में सड़क परिवहन की मांग में 12 से 15 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्वि होने का अनुमान लगाया गया हैं,

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं

(ग) क्या यह सच हैं कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने सड़क मार्ग परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए कानूनी अड़चनों को अब तक दर